भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 916
दिनांक 27.07.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग की वर्तमान स्थिति

916. श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः
श्री मस्तान राव यादव बीडाः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य विधानसभाओं तथा संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (एनईवीए) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) एनईवीए तथा अन्य डिजिटल संसदीय प्लेटफार्मों द्वारा विधायी कार्यों की दक्षता में, विशेष रूप से कागज़ के उपयोग में कमी लाने, प्रक्रमण के समय में कमी लाने तथा प्रशासनिक व्यय में बचत के संदर्भ में, किस हद तक सुधार हुआ है;
(ग) क्या एनईवीए तथा इससे संबद्ध अन्य डिजिटल प्लैटफार्मों के प्रदर्शन एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;
(ङ) क्या सरकार विशेष रूप से सुलभता, साइबर सुरक्षा, अंतर संचालनीयता तथा हितधारकों के बीच वास्तविक समय में समन्वय के संबंध में इन प्लैटफार्मों को और सुदृढ़ बनाने का विचार रखती है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 37 विधानमंडलों में से 33 विधानमंडल 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन' (नेवा) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से, 21 विधायी सदनों को नेवा परियोजना के अंतर्गत डिजिटल विधानमंडलों में परिवर्तित किया जा चुका है। संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण नेवा परियोजना के दायरे में नहीं आता है।

(ख) नेवा ने सदन के कामकाज की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग को संभव बनाकर विधायी कामकाज की कार्यक्षमता में सुधार किया है। इसने कागज़-आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम की है, विधायी कार्य की प्रोसेसिंग और सूचना के प्रसार को तेज़ और आसान बनाया है, विधायी सूचना तक पहुँच को बेहतर किया है और दस्तावेज़ों की छपाई, रखरखाव और भंडारण में लागत की बचत की है।

(ग) हां। नीति आयोग द्वारा नेवा परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है।

(घ) मूल्यांकन रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी देखा गया कि नेवा ने कागज़ के इस्तेमाल को कम किया है और विधायी कार्य-प्रवाह में सुधार किया है। विधायिका और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल से विधायी कामकाज तेज़ी से निपटाने में मदद मिली है और नेवा का पब्लिक पोर्टल विधायी दस्तावेज़ों तक रियल-टाइम पहुँच प्रदान करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्षमता-निर्माण की पहलों, जैसे कि नेवा सेवा केंद्रों की स्थापना, ने हितधारकों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देकर इस प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने में मदद की है।

(ङ) हाँ। उपयोगकर्ता फ़ीडबैक और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर नेवा एप्लीकेशन को समय-समय पर अपग्रेड किया जाता है।

(च) साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए नेवा एप्लीकेशन को सुरक्षित एनआईसी मेघराज 2.0 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित किया गया है। भाषिणी के साथ एकीकरण से पब्लिक पोर्टल की सामग्री का टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट अनुवाद संभव हो गया है, जिससे भाषाई पहुंच बेहतर हुई है। इस एप्लीकेशन को एक डिवाइस-एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म के तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि अलग-अलग डिवाइस पर इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। भूमिका आधारित डैशबोर्ड और विधायी दस्तावेजों की कार्यप्रवाह आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं, सदस्यों, विधानमंडल सचिवालयों और सरकारी विभागों जैसे अलग-अलग यूज़र रोल के बीच तालमेल सुनिश्चित करती हैं।

***